कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा किया गया है। वास्तविक ड्रिलिंग कार्य अंशतः विभागीय रिगों के माध्यम से और अंशतः मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०, राज्य सरकारी एजेंसियों आदि को कार्यरत करके किया जा रहा है। एक बार गृहीत खानों का विकास निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की अनुमति दिए जाने पर पट्टेदार, पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में अन्वेषण कार्य कर सकते हैं बशर्ते कि यह कार्य सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत हो।

कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के निकट कोयले के भंडार

3120. **श्री अजीत जोगी :**

श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से और आज की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के निकट गैर कोकिंग कोयले का अनुमानतः कितना भंडार पड़ा हुआ है और उसका मूल्य कितना है ; और

(ख) इन भंडारों का किस प्रकार निपटान किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० न्यामेगौड़ा) : (क) दिनांक 30-6-92 की स्थिति के अनुसार और पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० की खानों में अकोक्कर कोयले का कुल सूचित किया गया स्टाक नीचे दिया गया है :—

(अंतिम) (करोड़ रु० में)

निम्नलिखित दिनांक को स्थिति	मिलियन टन में भंडार	भंडार की कीमत*
30-6-92	26.14	841.71
31-3-92	30.31	975.98
31-3-91	26.56	661.34
31-3-90	26.28	704.17

*1990 और 1991 के लिए 249 रु० प्रति टन तथा 1962 के लिए 322 रु० प्रति टन की औसत कीमत मानते हुए।

(ख) इन पिटहैड स्टाकों को समाप्त करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) रेलवे लोडिंग के लिए उपलब्ध कोयले को रेलवे साइडिंग तक परिवहन करके वृद्धि की जा रही है, यहां तक कि रेलवे साइडिंग से 3 कि० मी० से अधिक की दूरी स्थित पिटहैडों के कोयले के स्टाक को भी रेलवे साइडिंग तक लाया जा रहा है।

(2) गृहीत माध्यमों जैसे रोप-वे, बल्ट, और मेरी-गो-राउन्ड प्रणाली के माध्यम से प्रेषणों को बढ़ाया जा रहा है।

(3) चूंकि सड़क से जुड़ी कोलरियों में बड़ी मात्रा में स्टाक उपलब्ध है, अतः बड़े उपभोक्ताओं जैसे विद्युत उपयोगिताओं और सीमेंट इकाइयों को सलाह दी गई है कि ऐसे स्रोतों आदि पर उपलब्ध कोयले का सड़क द्वारा उठान कर लिया जाए।

(4) सभी उपभोक्ताओं को पिटहैडों से 20 मि० टन कोयला जारी किए जाने की एक योजना शुरू की गई है, जिसमें वास्तविक उपभोक्ताओं को, बिना किसी प्रायोजकता के, प्राथमिकता दी जा रही है।

कोयले की पूर्ति के लिए भुगतान के निबंधन और शर्तों में संशोधन

3121. **श्री अजीत जोगी :**

श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कोयला की उक्त खपत वाले उद्योगों को कोयले की पूर्ति के लिए भुगतान के निबन्धन और शर्तों में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेल बैगनों की कमी के कारण विविध प्रकार के कोयले के आबंटन और वास्तविक लदान के बीच 15 दिन से 3 माह तक का अत्यधिक समय लग जाता है ;

(घ) मध्य प्रदेश में कुल कितने उद्योग कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं;

(ङ) आगामी वर्षों में कोयले की पूर्ति में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत कमी होने का अनुमान है ; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) (क) और (ख) कोल इंडिया लि० ने दिनांक 1-10-91 से कोयले की बिक्री की अग्रिम अदायगी की प्रणाली शुरु की है। यह प्रणाली केवल विद्युत क्षेत्र के लिए लागू की गई है। अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के संबंध में कोल इंडिया लि० विद्यमान प्रणाली ही जारी रखे हुए है।

(ग) कोल इंडिया लि० ने यह सूचित किया है कि रेलव लदान की तारीख से 24 से 28 घंटे की अवधि के बीच अग्रिम रूप में प्रतिदिन के आधार पर कोयला के वैगनों का आवंटन करता है। आमतौर पर आवंटित वैगनों में आवंटन किए जाने की तारीख से 1 दिन से 7 दिन के बीच की अवधि में लदान किया जाता है।

(घ) देश के गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति में कुछ कमी रही है जिसमें मध्य प्रदेश के उपभोक्ता भी शामिल हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे विद्युत, इस्पात, लोको, सीमेंट और उर्वरकों आदि को रेल द्वारा कोयले के संचलन में प्राथमिकता दिए जाने के कारण हुआ है। किंतु वर्ष 1991-92 के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं का कोयले की आपूर्ति लगभग उतनी ही मात्रा में की गई जितनी कि वर्ष 1990-91 के दौरान की गई थी। सरकार ने सभी कोयला कंपनियों को इस आशय के निर्देशन दे दिए हैं कि वह सभी गैर-महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को रेल अथवा सड़क द्वारा संयोजित मात्रा की न्यूनतम 50% आपूर्ति करें। कोल इंडिया लि० को यह भी सलाह दी गई है कि व सभी उपभोक्ताओं को पिटहैड स्टाक से अप्रतिबंधित आधार पर 20 मि० टन कोयला प्रदान करें। कोयला उपभोक्ता उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत इस योजना के तहत विनिर्दिष्ट की गई खानों से बिना किसी प्रायोजन के एक बार में 1000 टन तक कोयले को उठाये जाने की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) और (च) यह संभावना है कि देश में सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयले की उपलब्धता में आगामी वर्षों में वृद्धि हो जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिदृश्य के अनुसार योजना अवधि के दौरान कोयले की उपलब्धता और मांग के बीच काफी कमी होने की कोई संभावना नहीं है।

कोल इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता

3122. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान बजटीय सहायता के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड को कितनी धनराशि दी है ;

(ख) क्या वित्तीय विवशताओं को देखते हुए सरकार कोल इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता बंद करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) कौन-कौन सी कंपनियों (कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन) लगातार घाटे में चल रही है और उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) कौन-कौन सी कंपनियां लाभ अर्जित कर रही हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(च) अर्जित लाभ से पिछड़े हुए क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कोल इंडिया लिमिटेड क्या प्रयास कर रही है ?